

an>

Title: Need to provide financial assistance to cotton growers in Maharashtra.

श्री राजू शेटी (हातकणगले): किसी भी अनुसंधान में सुधार करने के लिए हमेशा अवसर रहता है। वही चीज कृषि अनुसंधान में भी लागू होती है। कोई-सी भी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, लेकिन वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जनता का शोषण (किसानों का) करके कमाया हुआ ज्यादा मुनाफा हमेशा बुरा होता है। इसी मुनाफे को "रॉयल्टी" जैसा प्यारा नाम दिया जाता है। होने वाले परिणामों की जिम्मेदारी न लेते हुए जनता का शोषण जमा किया हुआ ज्यादा रॉयल्टी भी हमेशा निषेध लायक है।

सदन के सभी सम्मानीय सदस्यों को पता होगा कि महाराष्ट्र में विरोध करके विदर्भ, मराठवाड़ा के कपास उत्पादन करने वाले किसानों को बी.टी. कॉटन का बीज कपास के प्लानटेशन के लिए वितरण किया गया। बी.टी. कॉटन (कपास) का प्रमाणित बीज बोलवर्म मुक्त उत्पादन के लिए इस्तेमाल कीजिए। इस प्रकार की गारंटी बीज उत्पादन कम्पनी ने किसानों को दी थी। यह सच है कि लेकिन हकीकत कुछ और ही है। 90 प्रतिशत कपास के क्षेत्र में बोलवर्म का प्रसार चारो ओर दिखाई दिया। इस प्रसार की वजह से कपास उत्पादक किसान का बड़ा घाटा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ कंपनियों ने हपने हाथ ऊपर कर दिए। इस वजह से कपास उत्पादक किसानों की खुदकुशी की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई।

टेक्नोलॉजी को लेकर हमारा विरोध नहीं है। लेकिन यह टेक्नोलॉजी किसान को देते वक्त बीज उत्पादक कंपनियों ने जो विज्ञापन (एडवर्टाईज) दिया था, उसी के तहत अगर किसान को उत्पादन नहीं आता तो उसको सही मुआवजा देना चाहिए और इस प्रकार से बीज का उत्पादन करते समय फील्ड ट्रायल लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर फील्ड ट्रायल टेस्टिंग में अगर बीज सही मात्रा में पास हुआ तभी किसानों के लिए मार्केट में बिक्री के लिए लाना चाहिए। कपास बीज उत्पादन करने वाली इन कंपनियों की वजह से महाराष्ट्र में जो किसानों का लाखों रुपयों का घाटा हुआ उनको बीज उत्पादक कंपनी और केंद्र सरकार द्वारा जल्द से जल्द आर्थिक मदद देने की जरूरत है।